RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 303
दि. 07.03.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुख्यमंत्री योगी ने 50 क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

सीएम ने कहा- शासन, प्रशासन और उद्योग जगत मिलकर प्रदेश के विकास और सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान कर रहे, पुलिस विभाग को दिए 50 क्यूआरटी दोपहिया वाहन

लखनऊ , (जीएनएस)। पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था किसी चुनाव में मुद्दा बनी और इसी का परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सरकार बनायी। पुलिस विभाग ने वर्ष 2017 के बाद बिगड़े, अराजक, दंगाग्रस्त और कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदल करके सेफ यूपी के रूप में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने की शुरूआत कड़ी सुरक्षा से ही होती है। विकास की पहली शर्त सुरक्षा है। इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबित किया है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन सभागार में कहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को 50 क्यूआरटी दोपहिया वाहन प्रदान किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी। यह समारोह उसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक है, जिसमें शासन, प्रशासन और उद्योग जगत मिलकर प्रदेश के विकास और सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

मॉडल पुलिसिंग के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का परसेप्शन चेंज करने के लिए कई कदम उठाए गए तो कुछ रिफॉर्म किये गये। इसके नतीजे हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्ष 2017 में पीआरवी के वाहन 9,500 थे। आज इनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। वहीं वर्ष 2017 में टू व्हीलर मात्र 3,000 थे। आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यह केवल संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की है। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई और सहायता पहुंचाएंगे, वही ट्रस्ट में बदलती है। वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉडल पुलिसिंग के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ बताएं हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी शामिल है।

वर्ष 2017 से पहले पुलिस विभाग का बजट अटकते-अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, लेकिन जिला मुख्यालय, पुलिस लाइन भी नहीं बनी थी। ऐसे में पुलिस क्या परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असलहे थे, कोई सुविधा नहीं थी। उस दौरान अवस्थापना सुविधाएं जीरो थीं। टूटे हुए बैरक में पुलिसकर्मी रहने को मजबूर थे। आज प्रदेश के 55 जिलों में सबसे ऊंची इमारत उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की बैरक है। यहां बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार मॉडल थानों और मॉडल फायर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पुलिस और आपदा सेवाओं को आधुनिक स्वरूप दिया जा सके।

पहले प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता केवल 3000 थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जब सरकार ने बड़े स्तर पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की तो उस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता बहुत सीमित थी। एक साथ लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सकता था। सरकार के सामने चुनौती थी कि लंबे समय से पुलिस भर्ती नहीं हुई थी और युवाओं में भर्ती को लेकर उत्सुकता थी, लेकिन प्रशिक्षण क्षमता सीमित होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कठिन था। किसी भी भर्ती प्रक्रिया को

पूरा करने में लगभग 9 महीने का समय लग जाता था। ऐसे में राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से संपर्क किया। दो-तीन राज्यों ने सहयोग के लिए सहमति दी।

इसके अलावा सेना और अर्द्धसैनिक बलों से भी बातचीत की गई, जिन्होंने सहयोग देने की बात कही। इन सभी प्रयासों के बाद किसी तरह प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाकर लगभग 17 से 20 हजार तक पहुंचाया गया। इसके बाद अन्य राज्यों तथा सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की मदद से इसे करीब 30 हजार तक ले जाया गया, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज प्रदेश में 60,244 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की गई है और इन सभी को उत्तर प्रदेश के अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में विकसित किए गए नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह संभव हो पाया है।

हर जिले में तैनात की गईं दो-दो मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई में देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए। इन कानूनों के तहत सात वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य किए गए हैं। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल दो फॉरेंसिक लैब थीं, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में विश्वस्तरीय स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन संचालित हो रहा है। इस संस्थान में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से पुलिस कर्मियों के साथ-साथ उन युवाओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनकी रुचि फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में है।

प्रत्येक जिले में ए-ग्रेड की छह फॉरेंसिक लैब निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा हर जिले में दो-दो मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी तैनात की गई हैं, जो घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संग्रह और जांच में मदद कर रही हैं। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए कई नई इकाइयों का गठन किया गया है। राज्य में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) का गठन किया गया है और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसके अलावा पहली बार पीएसी में महिला बटालियन का गठन किया गया है। अब तक तीन महिला बटालियन गठित की जा चुकी हैं और तीन नई बटालियनों के गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

सुरक्षित बेटियां और व्यापारी प्रदेश और देश के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास प्रारंभ किए गए। इन सभी को मिलाकर जब टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। यही कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार बनता है। आज देश और दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। इसका प्रमुख कारण राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति है। इसके साथ ही प्रदेश में हर बेटी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षा का अनुभव करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही प्रदेश और देश के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहले प्रदेश में पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, जिसके कारण बड़ी चुनौतियों का सामना करना कठिन हो जाता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश पुलिस हर बड़ी चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

विकास और पर्यावरण को विरोधी शक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब नागरिक जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनें: लोक सभा अध्यक्ष

समावेशी विकास के लिए विभागों और नीतियों के बीच 'ट्रांसवर्सैलिटी' आवश्यक है: लोक सभा अध्यक्ष

लोक सभा अध्यक्ष ने वॉटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवॉर्ड्स एवं कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित किया

(जीएनएस)।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कहा कि विकास और पर्यावरण को विरोधी शक्तियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें एक-दूसरे के पूरक के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है और जनप्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना

चाहिए।

श्री बिरला ने ये विचार वॉटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवॉर्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने जल संरक्षण, सतत विकास और वैश्विक सहयोग के महत्व पर बल दिया और कहा कि इंटरनेशनल वॉटर फोरम (क्ब्ऋ) जैसी पहलें जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

यह उल्लेख करते हुए कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब नागरिक जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनें, श्री बिरला ने बताया कि जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ऐसे क्षेत्र हैं जो गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन जटिल चुनौतियों का समाधान केवल समन्वित और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से ही संभव है।

प्रधानमंत्री 8 मार्च को दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपये की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के मजलिस पार्क - मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) और दीपाली चौक - मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण 5-ए विस्तार के तहत तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे

प्रधानमंत्री जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) पुनर्विकास योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

इन परियोजनाओं का पुनर्विकास एक अभिनव, आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल के माध्यम से किया गया है, जिससे सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित किया

इस वर्ष के केंद्रीय बजट ने कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को नई दिशा प्रदान की है: पीएम

सरकार ने कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूत किया है, प्रमुख प्रयासों से किसानों के जोखिम कम हुए हैं और उन्हें बुनियादी आर्थिक सुरक्षा मिली है: पीएम

यदि हम उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा दें, तो यह कृषि को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में बदल देगा: पीएम

निर्यात-उन्मुख उत्पादन बढ़ने से प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा: पीएम

मत्स्य पालन ग्रामीण समृद्धि के लिए एक उच्च मूल्य और उच्च प्रभाव वाला क्षेत्र और निर्यात वृद्धि का एक प्रमुख आधार बन सकता है: पीएम

सरकार एग्रीस्टैक के माध्यम से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर रही है: पीएम

प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है जब सिस्टम इसे अपनाएं हैं, संस्थान इसे एकीकृत करें हैं और उद्यमी इस पर नवाचार करें: पीएम

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बजट के बाद आयोजित तीसरे वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार का मुख्य विषय 'कृषि और ग्रामीण परिवर्तन' था। प्रौद्योगिकी और आर्थिक

विकास से संबंधित पिछले सत्रों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट तैयार करने के दौरान हितधारकों ने बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि अब बजट के बाद, यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि देश अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठाए और इस दिशा में आपके सुझाव और यह वेबिनार इसलिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और देश के दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री मोदी ने 'पीएम किसान सम्मान निधि' और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)' जैसे कई कार्यक्रमों पर बल दिया, जिनसे किसानों को डेढ़ गुना लाभ मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूत किया है।

मौजूदा योजनाओं की सफलता के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बीमा दावों का निपटारा किया गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि संस्थागत ऋण कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि इन अनेक प्रयासों से किसानों के जोखिम कम हुए हैं और उन्हें बुनियादी आर्थिक सुरक्षा मिली है।

खाद्यान्न और दालों के रिकॉर्ड उत्पादन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी की दूसरी तिमाही की शुरूआत के साथ ही इस क्षेत्र में नई ऊर्जा डालने का आ'ान किया। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में इस दिशा में किए गए नए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वेबिनार की चचाओं से बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस वेबिनार में हुई चर्चा और उससे प्राप्त सुझाव जमीनी स्तर पर बजट प्रावधानों को यथाशीघ्र लागू करने में सहायक साबित होंगे।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक मांग में हो रहे बदलावों और भारतीय कृषि को निर्यात-उन्मुख बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की विविध जलवायु का पूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि इस वेबिनार में, हमारी कृषि को निर्यात-उन्मुख बनाने पर अधिकतम चर्चा करना आवश्यक है।

उच्च मूल्य वाली कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कोको, काजू और चंदन जैसी फसलों के क्षेत्र-विशिष्ट संवर्धन के लिए बजट प्रस्तावों का विस्तृत विवरण दिया। श्री मोदी ने पूर्वोत्तर में अगरवुड और हिमालयी राज्यों में शीतोष्ण मेवों की फसलों को बढ़ावा देने के बजट प्रस्ताव पर भी प्रकाश डाला।

जीईएम ने समावेशी सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त पहल के सात वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया

स्वायत्त ने जीईएम के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और एसएचजी के लिए सरकारी खरीद तक पहुँच का विस्तार किया

महिला उद्यमियों ने जीईएम पर 83,323 करोड़ रुपये के ऑर्डर दर्ज किए; स्वायत्त के तहत स्टार्टअप्स ने 54,000 करोड़ रुपये का आँकड़ा पार किया

(जीएनएस)।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने आज अपनी प्रमुख पहल स्वायत्त - ई-लेन-देन के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवाओं को लाभ- के सात वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाते हुए देशभर के स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए सार्वजनिक खरीद को अधिक समावेशी बनाने की प्रतिबद्धता दोहरायी।

19 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई स्वायत्त पहल की परिकल्पना स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, युवाओं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अंतिम छोर के विक्रेताओं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाते हुए सरकारी खरीद प्रणाली को सर्वसुलभ बनाने के विजन के साथ की गई थी।

जीईएम के सामाजिक समावेशन के मूल सिद्धांत पर आधारित स्वायत्त पहल उभरते उद्यमों के समक्ष अक्सर आने वाली तीन प्रमुख चुनौतियों—बाजार तक पहुँच, वित्त तक पहुँच और मूल्य संवर्धन तक पहुँच —से निपटने पर केंद्रित है। जीईएम के डिजिटल खरीद से संबंधित बुनियादी ढाँचे का उपयोग करते हुए यह पहल देशभर के उद्यमों को सरकारी खरीदारों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रवेश की बाधाएँ कम होती हैं और अवसरों का विस्तार होता है।

स्वायत्त की सात वर्षीय यात्रा को चिह्नित करने के लिए जीईएम कार्यालय में एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ओडिशा के पारादीप में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र-III का लोकार्पण किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में ठऊङ्ग और डटञ्जक्रऊ के विकास कार्यों का उद्घाटन और ओडिशा सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ओडिशा के पारादीप में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र-क्कक्क का लोकार्पण किया और सहकारिता विकास गोष्ठी को भी संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

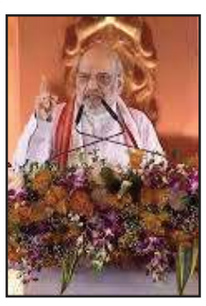

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन ओडिशा के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज एक ही दिन में 3770 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज पारादीप में इफ्को का सल्फ्यूरिक एसिड का विशाल कारखाना लोकार्पित हुआ जिसके माध्यम से इफ्को अब सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इफ्को और कृभको मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां गृह मंत्रालय की 3, सहकारिता मंत्रालय की 4 और ओडिशा सरकार की 173 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार की 173 योजनाओं में से 1230 करोड़ रूपए की लागत वाली 61 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 2116 करोड़ रूपए की लागत वाली 112 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहां गृह मंत्रालय के दो विशिष्ट प्रयोजन -ओडिशा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमिपूजन हुआ है और एक अस्थायी कैंपस का भी उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से ओडिशा के फोरेंसिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएट होते ही पक्की नौकरी वाले कोर्सेस के माध्यम से बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी जो देश की कानून और व्यवस्था को मजबूती देंगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां तीन नूतन न्याय संहिताओं को आम नागरिकों, वकीलों, न्यायपालिका के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों की समझ में आने वाली सरल भाषा में प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 150 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मेंभारत के संविधान के अनुरुप, भारतीय संसद से पारित और भारत के लोगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पारित कानूनों से अब देश चल रहा है।

हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट में फजीवाड़े का आरोप

लखनऊ। मानवेंद्र सिंह पटेल हिंद इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए है। उनका कहना है वर्ष 2004 में हुई डीड में मेन ट्रस्टी डॉ अमोद कुमार सचान, सुशीला चौधरी,डॉ हरीश चंद्रा, मिस ऋचा मिश्रा, सुनील कुमार वर्मा, ब्रिज किशोर सिंह,मधु चौधरी थे। ट्रस्टियों को गुमराह करते हुए ओरिजिनल स्टाम्प पर छेड़छाड़ कर डॉ अमोद कुमार ऋचा मिश्रा का नाम रखा गया, अब डॉ अमोद कुमार फजीर्वाड़ा करने के फिराक में है। उन्होंने प्रेस कांग्रेस के दौरान कहा कि हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट में फर्जी तरीके से सैकड़ों करोड़ का लोन कराया गया। बैंक ने बिना सर्वे जांच के लिए लोन स्वीकृत कर दिया। जब इसकी जानकारी ओरिजिनल ट्रस्टियों को हुई।जिसके बाद 2 फरवरी को थाना कैसरबाग में 156/3 में मुकदमा दर्ज कराया गया, ल्ढ़ील्ल' पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतना बड़ा लोन देने से पहले ट्रस्टियों के हस्ताक्षर की जांच करानी चाहिए थी जो कि नहीं

किया गया। इंस्टीट्यूट के मेन ट्रस्टियों ने ँ को मेल कर कहा जाली हस्ताक्षर पर कैसे लोन दे दिया गया। जबकि आम आदमी महज कुछ हजार का अगर लोन लेने किसी बैंक में जाता है तो उसके दस्तावेजों की कई बार जांच होती है उसके बाद ही लोन स्वीकृत किया जाता है। पटेल ने कहा कि डॉ सचान ने सपा विधायक अरमान व दर्जनों रायफल धारियों के साथ इंस्टीट्यूट में पहुंचने व तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया है।उन्होंने डॉ के साथ सपा विधायक अरमान खान व समर्थकों पर कॉलेज में जमा हुई फीस व अन्य सोर्स का पैसा करीब 2.5 करोड़ रु उठाने की बात भी कही।उन्होंने आगे कहा कि डॉ सचान ने कई बैंकों से धोखाधड़ी कर कॉलेज के नाम पर करीब 300 करोड़ का लोन कराया है जिसकी जानकारी किसी ट्रस्टी को नहीं है,हिंद मेडिकल कॉलेज वर्तमान समय में यूपी के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में गिना जाता है,उन्होंने कहा कि आखिर फर्जी स्टाम्प व फर्जी हस्ताक्षर पर कैसे ँ ने बिना सर्वे के लोन दे दिया था।मानवेंद्र पटेल ने कहा कि इतना ही नहीं डॉ सचान ने अपने पावर के दम पर फजीर्वाड़े पर फर्दा डालने के लिए ओरिजिनल ट्रस्टियों पर ही गलत तरीके से एफआईआर करा दी।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मामला इंस्टीट्यूट से जुड़ा है जिसमें हजारों छात्र छात्राएं पढ़ती है उनके भविष्य को देखते हुए इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच सरकार कराए जिससे एक बड़े भ्रष्टाचार से पर्दा उठ सके

उससे डॉ सचान की दबंगई का उदाहरण साफ देखा जा सकता है

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 16 से 28 फरवरी 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान मनाया गया।

(जीएनएस)।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने 16 से 28 फरवरी 2026 तक मनाए गए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और जागरूकता गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। यह स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

विभाग में वर्ष 2026 स्वच्छता पखवाड़ा के कार्यान्वयन का लगातार 11वां वर्ष है । प्रस्तावित गतिविधि कैलेंडर और विस्तृत दिशा-निर्देश डीएफपीडी से जुड़े सभी संगठनों और कार्यालयों को वितरित किए गए ताकि अभियान में प्रभावी भागीदारी और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

इस अभियान का शुभारंभ 16 फरवरी 2026 को एक उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इसमें डीएफपीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली और स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों का समर्थन करने के अपने संकल्प को दोहराया । यह शपथ डीएफपीडी के

अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस और एफए) के नेतृत्व में दिलाई गई। इसमें कार्यस्थलों और दैनिक जीवन में स्वच्छता की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस पखवाड़े के दौरान कई गतिविधियाँ चलाई गईं। इनमें एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण अभियान आयोजित करना शामिल था। स्वच्छता के महत्व को बताने वाले जागरूकता बैनर और पोस्टर विभाग के सभी कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए।

स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के विजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएफपीडी के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों ने प्रतिदिन इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वच्छ और स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण बनाने के लिए कार्यालय परिसर से अनावश्यक सामान हटाना, धूल झाड़ना और स्वच्छता बनाए रखना, कचरे का पृथक्करण करना और शौचालयों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई जैसे कार्य किए गए।

इस अभियान के अंतर्गत, सफाई मित्रों के बहुमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, कार्यालय परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए किए गए उनके समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए सफाई कर्मचारियों को उपहार भेंट किए गए।

विभाग ने निरंतर जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्वच्छता की भावना को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इससे स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र की व्यापक दृष्टि में मदद मिलेगी।

वर्ष 2025-26 के दौरान मुक्त व्यापार समझौतों में भारत की उपलब्धियां

(जीएनएस)।

भारत ने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में पिछले एक दशक में एक निर्णय लेने में सक्षम एवं आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनायी है। भारत ने वैश्विक व्यापार की दिशा को न केवल नए सिरे से परिभाषित किया है, बल्कि आधुनिक, भविषयोन्मुखी और नए दौर के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों के अपने दायरे को विस्तार दिया है और अब तक 38 देशों के साथ कुल नौ एफटीए तक अपनी पहुंच बनाई है। इसकी शुरूआत वर्ष 2021 में भारत-मॉरीशस समझौते से हुई। इसके बाद मई 2022 में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) लागू हुआ। दिसंबर 2022 में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ। इसके बाद भारत ने 10 मार्च 2024 को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ई एफ टी ए) के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टी ई पी ए) पर हस्ताक्षर किए, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। जुलाई 2025 में भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सी ई टी ए) पर हस्ताक्षर किए गए और दिसंबर 2025 में भारत-ओमान सी ई पी ए संपन्न हुआ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 22 दिसंबर 2025 को भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई और 27 जनवरी 2026 को भारत-यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर सहमति बनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी 7 फरवरी 2026 को एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनाकर भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी मजबूत उपस्थिति को और सुदृढ़ किया है।

दुनिया के अलग-अलग देशों और समूहों के साथ किया जाने वाला हर एक समझौता अपने आप में विशिष्ट है जो भारत के विशाल बाजार, भारत की आर्थिक क्षमता तथा 1.4 अरब भारतीयों की क्षमताओं पर वैश्विक भरोसे का प्रतीक है।

ये समझौते हमारे किसानों के लिए हैं, जिनके उत्पादों को अब विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच मिल रही है। ये हमारे उद्यमियों और महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई) के लिए हैं, जो परिधान, चमड़ा और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों का निर्यात नई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के साथ कर रहे हैं। ये समझौते हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए भी हैं—हमारे विद्यार्थी, आईटी पेशेवर, शेफ और योग प्रशिक्षक—जिन्हें अब काम करने, पढ़ाई करने और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए अधिक विकल्प और स्पष्ट गतिशीलता के अवसर मिल रहे हैं। इन समझौतों में विदेशों में पढ़ाई के बाद कार्य वीजा, पेशेवर गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी छूट के भी प्रावधान शामिल हैं। ये समझौते जैविक उत्पादों और आयुष की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं। साथ ही, ये डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र को भी सशक्त बनाते हैं, जो वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) के विकास को गति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त, ये समझौते निवेश को प्रोत्साहित करने और हमारे मुक्त व्यापार समझौता (एफ टी ए) साझेदार देशों को भारत की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बनाने का भी कार्य कर रहे हैं।

भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत खुलेपन, संतुलन और आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए की है। इन समझौतों में डेयरी, कृषि, किसानों और घरेलू उद्योग जैसे सभी संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा की गई है तथा बाजार तक पहुंच को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा गया है। यह भारत की मजबूत और आत्मविश्वासी वातार्कार क्षमता को दशार्ता है, जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार में परिवर्तन के एक नए युग की शुरूआत हो रही है और हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं को साकार किया जा रहा है। भारत विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने रांची में एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया

यूआईडीएआई आधार सेवाओं को और मजबूत कर रहा है, झारखंड रांची में आधार सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी

(जीएनएस)।

6 मार्च 2026 को, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने एस्टेट प्लाजा, कांटा टोली, रांची स्थित एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र (एएसके) का उद्घाटन किया। इस एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन रांची और आसपास के क्षेत्रों में आधार सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र को उन्नत तकनीकी सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया गया है ताकि आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं तेज, पारदर्शी और निवासियों के अनुकूल तरीके से प्रदान की जा सकें।सकें। इस आधार सेवा केंद्र के दैनिक संचालन का प्रबंधन प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

कई जिलों में आधार केंद्र खुलेंगे

पहले, झारखंड में यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्र केवल तीन जिलों रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में उपलब्ध थे। अब, मौजूदा केंद्रों के अलावा, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा और पलामू में चरणबद्ध तरीके से नए आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इस अवसर पर, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने यूआईडीएआई के

प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर और फिर 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर करवाएं, ताकि वे छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और नीट तथा सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं के पंजीकरण में किसी समस्या का सामना न करें।

कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने भी माता-पिता से बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कराने और स्कूलों से यूआईडीएआई की मिशन मोड कैंपेन के तहत एमबीयू बैकलॉग कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के उप निदेशक महानिदेशक अखिलेश कुमार गुप्ता और निदेशक नीरज कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग काउंटर*

कांटा टोली के आधार केंद्र में विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं ताकि उन्हें सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिल सके। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक फीडिंग रूम भी उपलब्ध कराया गया है। यहां जन्म पंजीकरण संख्या (बीआरएन)-आधारित बाल नामांकन भी लागू किया जा रहा है।

जीईएम ने समावेशी सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त पहल के सात वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया

स्वायत्त ने जीईएम के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और एसएचजी के लिए सरकारी खरीद तक पहुँच का विस्तार किया

महिला उद्यमियों ने जीईएम पर 83,323 करोड़ रुपये के ऑर्डर दर्ज किए; स्वायत्त के तहत स्टार्टअप्स ने 54,000 करोड़ रुपये का आँकड़ा पार किया

(जीएनएस)।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने आज अपनी प्रमुख पहल स्वायत्त - ई-लेन-देन के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवाओं को लाभ- के सात वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाते हुए देशभर के स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए सार्वजनिक खरीद को अधिक समावेशी बनाने की प्रतिबद्धता दोहरायी।

19 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई स्वायत्त पहल की परिकल्पना स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, युवाओं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अंतिम छोर के विक्रेताओं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाते हुए सरकारी खरीद प्रणाली को सर्वसुलभ बनाने के विजन के साथ की गई थी।

जीईएम के सामाजिक समावेशन के मूल सिद्धांत पर आधारित स्वायत्त पहल उभरते उद्यमों के समक्ष अक्सर आने वाली तीन प्रमुख चुनौतियों—बाजार तक पहुँच, वित्त तक पहुँच और मूल्य संवर्धन तक पहुँच —से निपटने पर केंद्रित है। जीईएम के डिजिटल खरीद से संबंधित बुनियादी ढाँचे का उपयोग करते हुए यह पहल देशभर के उद्यमों को सरकारी खरीदारों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रवेश की बाधाएँ कम होती हैं और अवसरों का विस्तार होता है।

स्वायत्त की सात वर्षीय यात्रा को चिह्नित करने के लिए जीईएम कार्यालय में एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नीति-निमार्ताओं, स्टार्टअप संस्थापकों, महिला उद्यमियों और इकोसिस्टम साझेदारों ने भाग लिया, जहां पहल के प्रभाव और इसके भविष्य के रोडमैप पर विचार किया गया।

कार्यक्रम की शुरूआत जीईएम के अपर सीईओ श्री अजीत बी. चव्हाण द्वारा स्वायत्त पर अपना परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ हुई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के विशेष संबोधन भी शामिल रहे, जिनमें एनईडीएआर फाउंडेशन के सह-संस्थापक और निदेशक श्री के. वी. राजेंद्रन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के निदेशक श्री मोहम्मद सालिक परवेज, तथा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के उप निदेशक श्री मोहम्मद आलम अंसारी शामिल थे।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों ने भी जीईएम के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में भागीदारी के अपने अनुभव साझा किए। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की संस्थापक श्रीमती नीलिमा मिश्रा और सरप्राइज समवन की संस्थापक सुश्री पिंकी माहेश्वरी ने बताया कि किस प्रकार जीईएम ने उनके उद्यमों को सरकारी बाजारों तक पहुँच बनाने और अपने व्यवसाय को विस्तार देने में मदद की है।

इस दौरान स्वायत्त की सात वर्ष की यात्रा को दशार्ने वाली एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें यह दिखाया गया कि इस पहल ने किस प्रकार देशभर में स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार किया है।

जीईएम के सीईओ श्री मिहिर कुमार ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि स्वायत्त पहल स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और युवाओं को सरकारी बाजारों तक सीधे पहुँच कायम करने में सक्षम बनाते हुए सार्वजनिक खरीद को अधिक समावेशी बनाने के जीईएम के विजन को साकार करती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और इकोसिस्टम की विभिन्न साझेदारियों का उपयोग करके जीईएम उभरते उद्यमों को देश की आर्थिक वृद्धि में सक्रिय भागीदार बनने में मदद कर रहा है।

मामूली विवाद में दलित युवक की पिटाई, लाइसेंसी बंदूक से दी जान से मारने की धमकी

खखरेरू / फतेहपुर थाना क्षेत्र के डुडियापुर मजरे जहांगीर नगर गहुरा गांव में मामूली विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक दलित युवक के साथ मारपीट करने और लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

गांव निवासी बाबूलाल पासवान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 मार्च 2026 की सुबह करीब 11:30 बजे गांव में आलोक दुबे और सोनकर बिरादरी के कुछ लोगों के बीच विवाद हो रहा था। उसी दौरान वह घर के लिए सामान लेने दुकान की ओर जा रहा था। आरोप है कि उसे देखते ही आलोक दुबे गाली-गलौज करने लगे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे सौरभ दुबे, आशीष व अन्य युवकों ने भी मिलकर उसके साथ मारपीट की।

पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान आलोक दुबे घर से लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक निकाल लाए और उसे लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे गांव में दहशत फैल गई। पीड़ित ने बंदूक लहराने का एक वीडियो भी पुलिस को सौंपने की बात कही है। हालांकि अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है जांच करके उचित कार्रवाई किया जाएगा

शादी समारोह में महिला से मारपीट, चार महिलाओं के खिलाफ तहरीर

खखरेरू / फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने आई एक महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने चार महिलाओं के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम औरहट निवासी जुबेदा बेगम पत्नी स्व. रईस अहमद ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह 6 मार्च को रहमतपुर गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। आरोप है कि दोपहर करीब 2:30 बजे रहमतपुर की रहने वाली नाहिद बेगम पत्नी तौफीक ने उन पर आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वहां मौजूद सना बानो, सबीना बेगम और इकरा बानो ने मिलकर उनके साथ लात-घूंसे से मारपीट कर दी।

पीड़िता का आरोप है कि इस घटना से वह काफी आहत हुई हैं। उन्होंने आरोपित महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज ओडिशा के मुंडली में सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया

वीरता, त्याग और बलिदान की पर्याय CISF आधुनिकता को अपनाकर राष्ट्र की सुरक्षा की ढाल बनी है

अपनी स्थापना के 56 वर्ष पूरे औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक पहुँचने वाली उक्त्र के बिना भारत के औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती

संसद से लेकर देश के प्रमुख संस्थानों और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में अपना लोहा मनवाने वाली उक्त्र अब देश के बंदरगाहों की सुरक्षा भी करेगी

मोदी जी ने 2047 तक देश को पूरी तरह विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें उक्त्र कैटेलिस्ट की भूमिका निभा रहा है

भारत के 70 हवाई अड्डों सहित 361 महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करने वाली उक्त्र को मोदी सरकार ने ड्रोन सुरक्षा में भी नोडल एजेंसी बनाया

आने वाले दिनों में उक्त्र निजी औद्योगिक समूहों को भी हाइब्रिड मोड में सुरक्षा देगी

नक्सलवाद को अंत के कगार पर लाने में CISF की अहम भूमिका रही है

तिरुपति से पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर का सपना देखने वाले नक्सलियों को 31 मार्च 2026 तक हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह परास्त कर देंगे

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज ₹890 करोड़ की लागत से उक्त्र से जुड़े 3 आवासीय परिसरों (कामरूप, नासिक और सीहोर) का शिलान्यास और 2 आवासीय परिसरों (राजरहाट और दिल्ली) का लोकार्पण किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज ओडिशा के मुंडली में उक्त्र के 57वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज ₹890 करोड़ की लागत से CISF से जुड़े 3 आवासीय परिसरों (कामरूप, नासिक और सीहोर) का शिलान्यास और 2 आवासीय परिसरों (राजरहाट और दिल्ली) का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी, केन्द्रीय गृह

सचिव और महानिदेशक, उक्त्र सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज 56 वर्ष पूरे कर उक्त्र औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक पहुंची है जो बल के पुरुषार्थ की गाथा है। उन्होंने कहा कि देश, देश के मजबूत अर्थतंत्र और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की संकल्पना औद्योगिक विकास के बिना नहीं हो सकती और औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक औद्योगिक सुरक्षा बल की जरूरत है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 56 साल में CISF ने न सिर्फ अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है बल्कि हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने कहा कि उक्त्र ने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि CISF ने वीरता, त्याग, बलिदान और भारत के समृद्ध इतिहास की परंपरा के साथ एकाग्रता को जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा दिखाया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना CISF के बिना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि CISF हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती के साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सारे बंदरगाहों की सुरक्षा उक्त्र को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 महत्वपूर्ण संकल्प देश की जनता के सामने रखे हैं - 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना और हर क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचना और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उक्त्र एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा रही है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उक्त्र कर्मियों के बलिदान ने हमेशा देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि CISF कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि आज यहां 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, अंतरराष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले पदक इस बात के साक्षी हैं कि हर क्षेत्र में CISF उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार रहती है। श्री शाह ने कहा कि अब तक 56 साल में वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,693 पदक प्राप्त करने वाली CISF ने एक बल के नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां ₹890 करोड़ की 5 अलग-अलग परियोजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि राजरहाट का आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी का आवासीय परिसर पूर्ण हो गया है जो हमारे जवानों और उनके परिजनों को सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि आज यहां CISF की वार्षिक पत्रिका का भी लोकार्पण हुआ है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज CISF भारत के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन सुरक्षा में भी उक्त्र को नोडल एजेंसी की भूमिका दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर तापविद्युत परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना, जैसी कई परियोजनाओं की सुरक्षा काम उक्त्र को सौंपा गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अब पोर्ट सुरक्षा संभालने के बाद देश की बहुत बड़ी समुद्री सीमा में आने वाले बंदरगाहों की सुरक्षा भी उक्त्र करेगा। उन्होंने कहा कि हमने 4 साल पहले CISF को हाइब्रिड मोड में एक मॉडल विकसित कर निजी औद्योगिक समूहों को भी सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था जो सर्वाधिक आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में CISF निजी औद्योगिक समूहों को भी हाइब्रिड मोड में सुरक्षा देगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 को हम देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी उक्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना में उक्त्र ने नक्सलरोधी अभियान में अपनी भूमिका निभाई है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

जेडीयू चाहती नीतीश रहे राजनीति में अधिक सक्रिय

राज्यसभा जाने के पैसले के बाद जनता दल (यूनाइटेड) संसदीय दल की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाईं और पार्टी के सांसदों, विधायकों, एमएलसी और वरिष्ठ नेताओं से गहन विचार-विमर्श के बाद एक बात सामने जरूर आईं कि जेडीयू नेतृत्व बिहार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करना चाहती है किन्तु इसके लिए वह पार्टी में किसी भी तरह का बिखराव नहीं होने देना चाहती। नीतीश सहित पार्टी के सभी बड़े नेता यह मानते हैं कि उनकी पार्टी में एकजुटता के लिए या तो नीतीश अगुवाईं कायम रहे या उनके पुत्र निशांत राजनीति में प्रावेश करें और सक्रिय रूप से संगठन में पैसले लें।यही कारण है कि शुक्रवार को बैठक में यह पैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि अब निशांत जेडीयू में शामिल किए जाएंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे। बैठक के पहले ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिह यानि लल्लन सिह ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री का चयन करेंगे चाहे वह जेडीयू का हो अथवा भाजपा का। लल्लन सिह की बात भी सही है। भाजपा का नेतृत्व मुख्यमंत्री का चयन नीतीश की इच्छा के विरुद्ध करना भी नहीं चाहता। नीतीश के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल उनकी पार्टी में ही आनी थी। कारण कि उनकी पार्टी में वुमा, ब्रा१ण और भूमिहार प्राभावशाली हैं किन्तु ये तीनों नीतीश की बात तो मानते हैं किन्तु यदि किसी एक जाति का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो शेष दो जातियां नाराज होकर पार्टी के हितों के खिलाफ सक्रिय हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि नीतीश न सिर्प अपने बेटे निशांत को राजनीति में सक्रिय करें बल्कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनवाएं जो उनके साथ समन्वय बनाकर चल सके। सच तो यही है कि भाजपा का संख्या बल चाहे जितना बड़ा होता, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बनते किन्तु जिस तरह उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है और उन्होंने अण्ड-बण्ड बयानबाजी करना शुरू किया है, उससे राज्य सरकार की बदनामी हो रही थी। एक आम धारणा यह बन चुकी थी कि बिहार में सरकार अफसरशाही चला रही है। इसका नुकसान दोनों ही पार्टियों को होता। इसलिए नीतीश ने बिना किसी हिचक के राज्यसभा जाना स्वीकार कर लिया। यदि नीतीश का स्वास्थ्य अच्छा होता तो वे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होते। लब्बोलुआब यह है कि इस वक्त जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही दिशा भी है। यदि पार्टी नेतृत्व ने समझदारी से कार्यकताओं को वास्तविकता का एहसास नहीं कराया तो जेडीयू अवसाद की शिकार हो सकती है और स्थानीय स्तर पर भाजपा के साथ टकराव भी हो सकता है। इन सभी सच्चाइयों को नीतीश समझ रहे हैं इसलिए उन्होंने महसूस किया कि अब पार्टी को एकजुट रखना और पुत्र निशांत को राजनीति में सक्रिय करना ही उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। नीतीश और उनकी पार्टी के शीर्ष नेता यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के 25 पर सिमटने के बाद निष्ठा में बदलाव का विकल्प बिल्वुल समाप्त हो चुका है, इसलिए राजनीति में सत्ता सुख चाहिए तो भाजपा के साथ बने रहना जरूरी है। नीतीश इस सच्चाईं को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज भाजपा अटल-आडवाणी की नहीं है जो नीतीश के लिए अपनी पार्टी के हितों के साथ समझौता करने को गलत नहीं मानते थे। किन्तु आज पार्टी मोदी-अमित शाह की है जो खुद को पार्टी का ट्रस्टी मानते हैं और सौदेबाजी को ये दोनों नेता अपना कर्तव्य समझते हैं। पार्टी के हितों के प्राति समर्पित नेतृत्व एक सीमा से ज्यादा अपने सहयोगी पार्टी को छूट देने की स्थिति में नहीं होता। वुल मिलाकर नीतीश भले ही स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट नहीं हैं किन्तु वह इतने भी बीमार नहीं हैं जिनका मस्तिष्क भाजपा, जेडीयू संबंधों की हकीकत न

बिहार बीजेपी के सामने नीतीश का चक्रव्यूह! दिल्ली जाने से नहीं सुलझेंगी सियासी गुत्थियां, जानें अंदर का सच

(जीएनएस)।

बिहार की राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद बिहार की राजनीति कौन सी करवट लेगी, इसे लेकर चचाओं का बाजार गरम है। सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी की रणनीति भले सफल हो गई हो, लेकिन बिहार में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है।

पटनाः राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने भर से बीजेपी की राजनीतिक राहें बिहार में आसान होने नहीं जा रही है। पिछले तीन दशक के शासन काल में नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन के इतने सारे मिल के पत्थर,खड़े किए हैं जो हर कदम पर आईने दिखाते रहेंगे। केवल नीतीश कुमार के दिल्ली चले जाने से किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने भर से नीतीश के वोटर में जितना आक्रोश है उसका असर देखिए। जदयू विधायक नीतीश कुमार को राज्यसभा चुनाव हराने के तरकीब और कानूनी सलाह लेने लगे हैं। नाराज कार्यकर्ता जदयू कार्यालय में तोड़फोड़ करने लगे है।

जेडीयू के अंदर हलचल क्यों?

कार्यकर्ता जदयू के भीतर विभीषण खोज रहे हैं। नारा भी काफी उत्तेजना से भरा है। जूते मारो, जदयू के गद्दारों को। हद तो यह हो गई कि बिहार के चौक के चौराहों पर लालू और नीतीश कुमार के जिंदाबाद तक के नारे लगने लगे। गौर करें तो लालू यादव और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे से उस गोलबंदी की याद दिला दी जो वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। तब महागठबंधन यानी जेडीयू-आरजेडी-कांग्रेस ने 178 सीटें जीतीं, एनडीए ने 59 सीटें और अन्य को 6 सीटें मिलीं थी। दरअसल एनडीए सत्ता में जब कभी बनी तो वह नीतीश कुमार के कारण बनी रही। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार के कारण कुर्मी,कुशवाहा, कहार,धानुक ,अत्यंत पिछड़ी जातियां और विकास

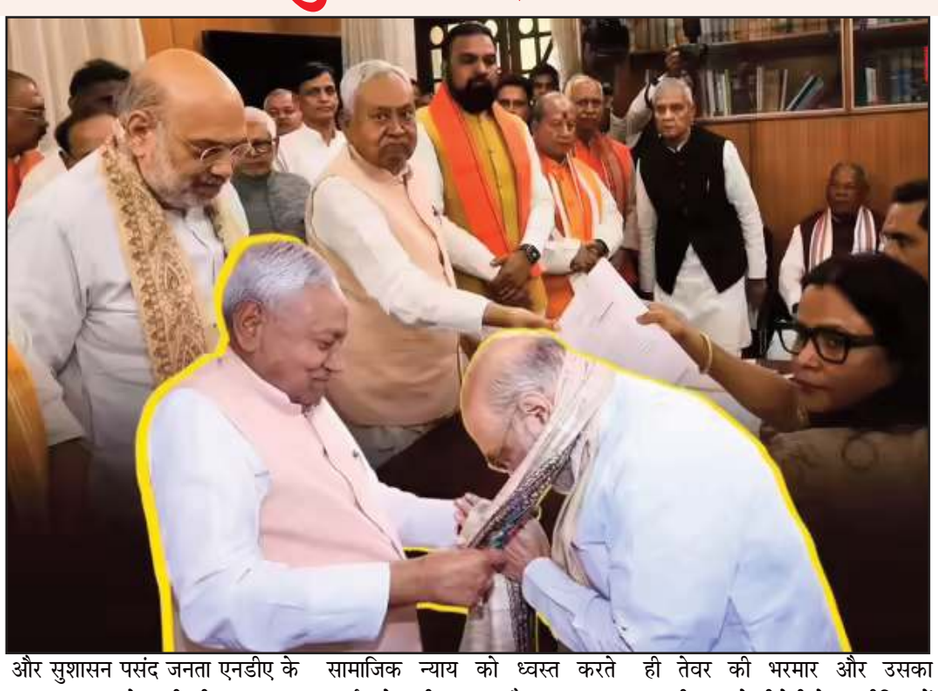

और सुशासन पसंद जनता एनडीए के रथ पर सवार हो जाती थी।

बीजेपी की राजनीति

बीजेपी सवर्ण और वैश्य की राजनीति कर लालू यादव के सामाजिक न्याय को ध्वस्त करते आई। ये वही राजद और जदयू का इकट्ठे उद्घोष हुआ करता था कि लालू यादव जंगल राज के नहीं सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। पिछल दिनों ऐसे ही तेवर की भरमार और उसका प्रकटीकरण ने बीजेपी के रणनीतिकारों की गति को रोक दिया। हाल तो यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपना की तरह राज्यसभा चुनाव को देख रहे हैं। पर जिस जनता के वे नायक हैं वे क्यों उनके चेहरा में उदासी और भय का संसार देख रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं- विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा जाऊंगा। पर उनके समर्थक उसमे क्यों झूठ ढूंढ रहे हैं।

बीजेपी की मुश्किलें?

भाजपा की मुश्किले इस बात को ले कर भी बढ़ने वाली है कि साथी दल भी असहज हैं। चिराग पासवान ने तब यह कहा भी था कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब विपक्ष के आरोपों के बीच जदयू विखंडन से जूझ रहा है और अब यह पार्टी खत्म हो जाएगी। स्वर तो यह भी गूंजने लगे कि रालोमो पर भी बीजेपी ने मर्जर का दबाव बना दिया है। बीजेपी की राजनीति में आए इस बदलाव के बाद विपक्ष आक्रामक है और एनडीए के साथी दल अपनी बारी के इंतजार में।

महिला दिवस पर कलर्स की प्रमुख अभिनेत्रियाँ बता रही हैं कि उनके लिए सशक्तिकरण का क्या अर्थ है।

प्रियंका चाहर चौधरी, जो कलर्स के सुपरनैचुरल शो 'नागिन' में अनंता का किरदार निभा रही हैं, कहती हैं 'मैं चार बहनों वाले परिवार में पली-बढ़ी हूँ, इसलिए मजबूती हमारे जीवन का स्वाभाविक तरीका था। हमें हमेशा यह सिखाया गया कि स्वतंत्र होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी है। मेरे पिता हमेशा कहते थे - 'अगर तुम दुनिया में कदम नहीं रखोगी, तो सीखोगी कैसे?' मैंने देखा है कि महिलाओं पर लगाए गए कई प्रतिबंध उनकी क्षमता से नहीं, बल्कि सोच और परवरिश से आते हैं। मुझे यह अवसर मिलने का सौभाग्य है कि मैं नागिन में सर्प रानी अनंता का रूप लेकर शक्ति का प्रदर्शन कर सकूँ। हमारी संस्कृति में हम अक्सर देवी शक्ति और महादेव की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि यह प्रतीकवाद यूँ ही नहीं है। शक्ति और सौम्यता साथ-साथ रह सकती हैं। मेरी इच्छा है कि और महिलाएँ अपनी 'सुपरपावर' पहचानें - चाहे वह कोई हुनर हो, कोई कला हो या कोई जन्मजात गुण। हर महिला को महिला दिवस की शुभकामनाएँ, जो अपनी प्रखर और कोमल दोनों ही पक्षों को अपनाती है।'

मानसी साल्वी, जो कलर्स के शो 'महादेव एंड सन्स' में भानु का किरदार निभा रही हैं, कहती हैं - 'मुझे अच्छा लगता है कि महिला दिवस लोगों को रुककर यह सोचने पर मजबूर करता है कि महिलाएँ रोजाना किन परिस्थितियों से गुजरती हैं। लेकिन यह ठहराव सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे साल हमारी सोच बदलनी चाहिए। आज मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करता है यह देखना कि महिलाएँ कितनी मजबूती से एक-दूसरे के लिए खड़ी हो रही हैं। उस बहनापे में एक शांत शक्ति है - सीमाएँ तय करने में, 'ना' कहने में और उसके लिए माफी न माँगने में। भानु भी ऐसी ही महिला है। वह अपने विश्वासों पर अडिग रहती है, चाहे हालात कितने भी उलझे क्यों न हों। शो का नाम भले ही महादेव एंड सन्स है, लेकिन असल में कहानी को आगे बढ़ाने वाली और अपनी शक्ति गढ़ने वाली महिलाएँ ही हैं। इस महिला दिवस पर मेरी आशा है कि और महिलाएँ अपनी आवाज पर भरोसा करें, जगह बनाएँ और खुद पर शक करना बंद करें।'

कश्मीरा शाह, कलर्स के शो 'लाफ्टर शेफ़्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' से, कहती हैं 'मेरे लिए महिला दिवस बड़े-बड़े बयानों से कम और महिलाओं की रोजमर्रा की ताकत को स्वीकारने से ज्यादा जुड़ा है। अब जब मैं दो बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे एहसास हुआ है कि उदाहरण देकर नेतृत्व करना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे हमेशा देखते हैं कि मैं कैसे बोलती हूँ, दबाव को कैसे संभालती हूँ और अपने लिए कैसे खड़ी होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे मजबूत महिलाओं का सम्मान करें, उनसे डरें नहीं। मैं चाहती हूँ कि वे समझें कि आत्मविश्वास किसी महिला में सामान्य है। मैंने कभी खुद को छोटा करने में विश्वास नहीं किया ताकि हालात दूसरों के लिए आसान हो जाएँ। अगर मेरी राय है, तो मैं कहूँगी। अगर मैं असहमत हूँ, तो मैं व्यक्त करूँगी। महिलाओं को बहुत सालों तक यह सिखाया गया है कि वे 'एडजस्ट' करें, नरम रहें और 'बहुत ज्यादा' न हों। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक ऐसी महिला देखें जो ईमानदार है, मेहनती है और खुद के प्रति आश्वस्त है। लाफ्टर शेफ़्स पर मैं कोई किरदार नहीं निभाती, मैं बस खुद को दिखाती हूँ - ईमानदार, अभिव्यक्तिपूर्ण, कभी तेज और कभी भावुक। यही असली है। और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उपहार यही है - अपनी प्रामाणिकता। मैं हर महिला से कहूँगी - दूसरों की सुविधा के लिए खुद को एडिट मत करो। सही लोग आपके साथ रहेंगे। महिला दिवस की शुभकामनाएँ हर उस महिला को जो अपनी राह खोज रही है। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं।'

ऐश्वर्या खरे, जो कलर्स के शो 'डॉ. आरंभि' में शीर्षक भूमिका निभा रही हैं, कहती हैं 'इस महिला दिवस पर मैं भारत की गृहिणियों को दिल से सलाम करना चाहती हूँ - वे महिलाएँ जो घर को रानी की तरह चलाती हैं। उनमें से कई ने डॉ. आरंभि में अपना प्यार डाला है और मैं आभारी हूँ कि इस शो के जरिए ऐसा असर बना सकी। यह बेहद भावुक कर देने वाला है कि महिलाएँ कहानी में दिखाई गई आत्म-त्याग को पहचानती हैं और लाखों दर्शक आरंभि के उठने का समर्थन कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब महिलाएँ और लड़कियाँ आरंभि की यात्रा से प्रेरणा लें - अपनी पहचान वापस पाने और डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने का साहस। इस महिला दिवस पर मैं हर महिला को याद दिलाना चाहती हूँ - आपके सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर कोई सपना अब भी आपको पुकार रह

'कॉटन एंड सिल्क फैब प्रदर्शनी 2026' का भव्य शुभारंभ

होली व चैत्र नवरात्रि स्पेशल

लखनऊ। होली और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में 'कॉटन एंड सिल्क फैब प्रदर्शनी 2026' का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मोहनलालगंज के विधायक अमरेश कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य नागरिक, और बड़ी संख्या में खरीदार मौजूद रहे।

इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 100 से अधिक मास्टर बुनकरों द्वारा तैयार किए गए एथनिक और पारंपरिक सिल्क व कॉटन हैंडलूम उत्पादों का शानदार संग्रह प्रदर्शित किया गया है। यहां बनारसी, चंदेरी, कांजीवरम और टसर सिल्क जैसे पारंपरिक वस्त्रों के साथ आधुनिक डिजाइन के आकर्षक परिधान भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा कश्मीरी प्योर क्रेप की साड़ियां, प्योर सिल्क मार्क अप्रूव्ड साड़ियां तथा कई विशेष हैंडलूम उत्पाद भी प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं।

प्रदर्शनी में आए आगंतुकों ने यहां उपलब्ध वस्त्रों की गुणवत्ता, डिजाइन और विविधता की सराहना की। पारंपरिक शिल्प और आधुनिक फैशन का सुंदर संगम इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है, जो फैशन प्रेमियों और पारंपरिक परिधानों के शौकीनों को खासा आकर्षित कर रहा है।

आयोजक मानस आचार्य और जावेद मकसूद ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के बुनकरों को एक मजबूत मंच प्रदान करना और लोगों को भारतीय सिल्क व हैंडलूम की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है और भारतीय हस्तकरघा उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलता है।

आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे प्रदर्शनी में आकर देश के कुशल बुनकरों के हुनर को देखें और भारतीय सिल्क व हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा दें। यह प्रदर्शनी आगामी दिनों तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।

होंडा इंडिया फाउंडेशन ने 'सड़क सहायकः सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन' परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को 50 कस्टमाइज्ड होंडा सीबी 350 क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) वाहन सौंपे।

राज्य में सड़क सुरक्षा, सामुदायिक कल्याण और तेज आपातकालीन प्रतिक्रिया को समर्थन।

लखनऊ, 06 मार्च 2026: सुरक्षित समुदायों के निर्माण में सहयोग देने और 2050 तक टक्कर-मुक्त समाज के होंडा के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, होंडा इंडिया फाउंडेशन (HIF) जो भारत में होंडा समूह की सभी कंपनियों की उरफ शाखा है ने अपने 'सड़क सहायकः सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन' प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को 50 विशेष रूप से सुसज्जित होंडा CB350 क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) वाहन सौंपे।

यह पहल होंडा इंडिया फाउंडेशन के व्यापक सड़क सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में जमीनी स्तर पर गतिशीलता बढ़ाना, आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करना और सुरक्षित सड़क प्रबंधन को समर्थन देना है।

सड़क सुरक्षा पहलों को मजबूत करने के लिए गुजरात, चंडीगढ़, कर्नाटक और राजस्थान पुलिस को 300 से अधिक होंडा दफ्छ वाहन पहले ही सौंपे जा चुके हैं। यह सहयोग सड़क सुरक्षा और समुदाय की मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए होंडा इंडिया फाउंडेशन की सार्वजनिक-निजी साझेदारी पर लगातार फोकस को दशार्ता है। यह पहल सुरक्षित सड़कों और बेहतर तरीके से प्रबंधित ट्रैफिक सिस्टम के साझा विजन को भी उजागर करती है।

यह समारोह लखनऊ के लोक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल, गृह एवं सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (लॉजिस्टिक्स) श्री राम कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) श्री अमिताभ यश और होंडा इंडिया फाउंडेशन के सलाहकार तथा होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री पीयूष मित्तल सहित उत्तर प्रदेश पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर दफ्छ वाहनों का औपचारिक हस्तांतरण किया गया।

होंडा उइ350 पर आधारित ये दफ्छ वाहन रिवॉल्विंग फ्लैशर और ब्लिंकर, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, सायरन, फ्लैशलाइट, साइड और रियर स्टोरेज बॉक्स तथा दो होंडा सेफ्टी हेलमेट से सुसज्जित हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य पुलिस टीमों को घनी आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करना है। ये वाहन आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने और पुलिस कर्मियों को अपने दायित्वों को प्रभावी और सुरक्षित तरीके से निभाने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए गए हैं। गतिशीलता और फुर्ती को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए ये वाहन अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थानों तक तेजी से पहुंचने में मदद करते हैं, जिससे जान बचाने, चोटों को कम करने और जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था की कार्यक्षमता बेहतर बनाने में सहायता मिलती है।

सोनालीका ने फरवरी में अब तक की सर्वाधिक 12,890 कुल ट्रैक्टर बिक्री दर्ज की

जैसे-जैसे देश के अलग-अलग क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीक से उन्नत और किफायती कृषि रही है, सोनालीका उत्पादों में नए इनोवेशन, किसानों से मजबूत जुड़ाव और तेज बाजार पहुंच के माध्यम से लगातार आगे बनी हुई है।

लखनऊ, 6 मार्च 2026 : देश में कृषि मशीनीकरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अपने 30वें ऐतिहासिक वर्ष में, सोनालीका ट्रैक्टर्स ने एक और सुनहरा अध्याय जोड़ते हुए वित्त वर्ष '26 में फरवरी माह की अब तक की सर्वाधिक 12,890 ट्रैक्टरों की कुल बिक्री दर्ज की है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि बड़े स्तर पर मजबूत कार्या नीति और कंपनी के मूल विश्वास 'जीतने का दम' का प्रमाण है — जो किसानों के उज्ज्वल भविष्य की ताकत है। आज जब देश में आधुनिक कृषि तकनीक से उन्नत और किफायती कृषि रही है, सोनालीका इनोवेशन, किसानों से गहरा जुड़ाव और मजबूत बाजार पहुंच के साथ लगातार आगे बढ़ रही है।

भारत का कृषि क्षेत्र इस समय एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है,

जहाँ सरकारी नीतियों का सहयोग, डिजिटल पहल के माध्यम से बढ़ता मशीनीकरण, आसान ऋण सुविधा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश किसानों की आय और उत्पादकता को मजबूत बना रहे हैं। सोनालीका ने हमेशा वैश्विक स्तर की इंजीनियरिंग को अपनाते हुए भविष्य के लिए तैयार ट्रैक्टर विकसित किए हैं, जैसे की हाल ही में लॉन्च की गई सोनालीका गोल्ड सीरीज, जो जमीनी कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप है और सोने की तरह सुरक्षित एवं दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करती है।

इस नई उपलब्धि पर अपने विचार साझा करते हुए, श्री रमन मित्तल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ने कहा, 'असली 'जीतने का दम' हमेशा उन किसानों में रहा है, जो हर दिन अपने खेतों में प्रगति बोते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर तैयार करें जो किसानों के सपनों और उनकी सफलता के संकल्प को और मजबूत बनाएं। भारत के कृषि परिवर्तन में हमारी भूमिका को और मजबूत करती है और हमें किसानों की प्रगति को देश की समृद्धि से जोड़ने की नई प्रेरणा देती है।'

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 5.67 लाख यूनिट बिक्री के साथ मजबूत वृद्धि दर्ज की

पिछले वर्ष की तुलना में कुल बिक्री में 34% की सालाना वृद्धि दर्ज की

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने फरवरी 2026 में कुल 5,67,351 यूनिट की बिक्री दर्ज की। इसमें 5,13,190 यूनिट घरेलू बाजार में और 54,161 यूनिट निर्यात के रूप में शामिल हैं।

कंपनी ने फरवरी 2025 की तुलना में 34% की सालाना वृद्धि दर्ज की। यह प्रदर्शन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एचएमएसआई के उत्पाद पोर्टफोलियो की मजबूत मांग को दशार्ता है।

वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) की वर्ष-से-तारीख अवधि के दौरान, एचएमएसआई ने कुल 58,20,556 यूनिट की बिक्री दर्ज की। इसमें 52,37,169 यूनिट घरेलू बिक्री और 5,83,387 यूनिट निर्यात शामिल हैं।

प्रदेश के अस्पतालों में 8,689 डॉक्टरों के पद खाली, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप का हमला

प्रदेश के अस्पतालों में 8,689 डॉक्टरों के पद खाली, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप का हमला

'स्वस्थ उत्तर प्रदेश' का दावा सफेद झूठ, राजधानी से गांव तक अस्पतालों में डॉक्टर नदारद

लेवल-2 और लेवल-3 में हजारों पद खाली, उल्टा-ढल्टा पर सबसे ज्यादा असर

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, दवा और जांच तक नहीं, गरीब निजी अस्पतालों में लुटने को मजबूर

2026 में भी एक्सरे की फिल्म नहीं, मशीनें धूल फांक रहीं, क्या 'जादू' से होगा इलाज?: वंशराज दुबे

(जीएनएस)।

लखनऊ। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'स्वस्थ उत्तर प्रदेश' का दावा पूरी तरह सफेद झूठ साबित हो रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 8,689 पद खाली पड़े हैं और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी भारी अभाव है। इसका सीधा असर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और जिला अस्पतालों पर पड़ रहा है जहां मरीजों को इलाज के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और कई बार डॉक्टरों की अनुपस्थिति में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है वंशराज दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने का दावा करती है लेकिन हकीकत यह है कि राजधानी लखनऊ से लेकर सुदूर गांवों तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। 8,600 से अधिक पदों का खाली होना यह बताता है कि भाजपा सरकार के लिए जनता के स्वास्थ्य की कोई प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण गरीब मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां उनसे मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े खुद सरकार की पोल खोल रहे हैं। विभाग में लेवल-2 के 7,240 पदों में से 5,497 पद खाली हैं, जबकि लेवल-3 के 5,199 पदों में केवल 2,007 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। यही नहीं, वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर भी भारी कमी है। संयुक्त निदेशक के 2,555 पदों में से 1,330 पद खाली, एडिशनल डायरेक्टर के 70 पदों में से 58 पद रिक्त, जबकि डिप्टी डायरेक्टर (सर्जन) के 970 पदों में से 157 पद खाली हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर मैनपावर संकट से जूझ रही है। दुबे ने कहा कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 2,391 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें 601 विशेषज्ञ डॉक्टर और 1,790 एमबीबीएस डॉक्टरों के पद शामिल थे। इसके लिए आवेदन भी लिए गए और जनवरी में इंटरव्यू भी आयोजित हुए लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी भर्ती का परिणाम घोषित नहीं हुआ और पूरी प्रक्रिया मेरिट व पारदर्शिता के विवाद में उलझ गई। इससे यह साफ हो गया है कि भाजपा सरकार

युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर कटवाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। उन्होंने कहा कि लेवल-2 और लेवल-3 डॉक्टरों की भारी कमी का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। सीएचसी और पीएचसी जैसे अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण गरीब और ग्रामीण मरीजों को इलाज के लिए या तो शहरों की ओर भागना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने को मजबूर होना पड़ता है। कई जगहों पर सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि वहां सिर्फ पर्चा काट दिया जाता है लेकिन इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होती। वंशराज दुबे ने अपने चित परिचित अंदाज में योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जुमलेबाजी से बीमारियां ठीक नहीं होतीं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता हिंदू-मुस्लिम की राजनीति और बुलडोजर की कार्रवाई से ऊपर उठकर कभी जनता के स्वास्थ्य पर भी होती, तो आज उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के अभाव में लोग दम नहीं तोड़ रहे होते। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को अस्पताल की दवा देने के बजाय बाहर के मेडिकल स्टोर का पता बताते नजर आते हैं। गरीब मरीजों को अपनी गाढ़ी कमाई से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। यह सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट है जो सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं को मरीजों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। सरकार के आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के दावों पर कटाक्ष करते हुए दुबे ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक स्थिति है कि साल 2026 में भी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में एक्सरे की फिल्म तक उपलब्ध नहीं है। मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट फोटोकॉपी के कागज पर दी जा रही है। कई अस्पतालों में आधुनिक जांच मशीनें या तो मौजूद नहीं हैं और जहां हैं भी, वहां बजट और रखरखाव के अभाव में धूल फांक रही हैं। सवाल यह है कि बिना फिल्म और बिना मशीनों के आखिर इलाज कैसे होगा? क्या सरकार जादू से मरीजों को ठीक करने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के सभी खाली पदों पर तत्काल पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाए, सरकारी अस्पतालों में दवाओं और जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना लागू की जाए। यदि सरकार जल्द इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है तो आम आदमी पार्टी जनता के स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पश्चिम एशिया के विकसित हो रहे समुद्री परिदृश्य के बीच निगरानी और तैयारियों को मजबूत किया

भारतीय समुद्री यात्रियों, जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री व्यापार की निरंतरता के लिए उपाय सक्रिय

बड़े बंदरगाहों को व्यापार संचालन में सहायता प्रदान करने और निर्यातकों को राहत देने का निर्देश

(जीएनएस)।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे युद्ध घटनाक्रम से बदल रहे समुद्री परिदृश्य के मद्देनजर निगरानी और तैयारी उपायों को मजबूत किया है। इसमें भारतीय समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भारतीय जहाजों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की निरंतरता बनाए रखना मुख्य फोकस है।

एमओपीएसडब्ल्यू के सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकसित हो रही स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विदेश मंत्रालय (MEA), महानिदेशक, विदेश व्यापार, (DGFT) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) शामिल थे। इसमें शिपिंग उद्योग और व्यापार संगठनों जैसे RIL, क्यूराज, CSLA और FIEO के हितधारकों ने भी भाग लिया।

यह समीक्षा माननीय केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पहले से बदल रहे समुद्री परिदृश्य की समीक्षा बैठक की अगली कड़ी थी।

मंत्रालय ने सभी हितधारकों को भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से मोपीएसडब्ल्यू द्वारा, मध्य पूर्व में विकसित हो रही स्थिति से बाद उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। एमओपीएसडब्ल्यू शिपिंग उद्योग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) में 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित की गई है ताकि समुद्री यात्रियों के लिए समन्वय और समर्थन सुगम हो।

एमओपीएसडब्ल्यू में माहौल को लगातार ट्रैक करने के लिए निगरानी तंत्र भी स्थापित किया गया है।भारतीय समुद्री यात्रियों, भारतीय ध्वज वाले जहाजों और समुद्री व्यापार संचालन की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने के उपायों का सलाह जारी किया गया है, जो DGS सर्कुलर नंबर 08 ऑफ 2026 दिनांक 28 फरवरी 2026 के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें सभी भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारतीय समुद्री यात्रियों को उन्नत सुरक्षा उपाय अपनाने और DGS सर्कुलर 08 ऑफ 2024 के तहत रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, DGS सर्कुलर नंबर 09 ऑफ 2026 दिनांक 28 फरवरी 2026 के माध्यम से क्रू सेफ्टी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारतीय समुद्री यात्रियों और शिपिंग हितधारकों को तत्काल निर्देश दिए गए हैं। इनमें भारत के तेहरान दूतावास में पंजीकरण और डायरेक्टोरेट को क्रू विवरण जमा करना शामिल हैं।

भारतीय ध्वज वाले जहाज सुरक्षित बने हुए हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ किसी भी पुष्ट हिरासत, चढ़ाई या हादसे की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फारस की खाड़ी क्षेत्र (होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में 24 और पूर्व में 11, जिसमें ओमान की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र शामिल) में मौजूद सभी 35 भारतीय ध्वज वाले जहाजों और एडेन की खाड़ी में 03 जहाजों को छब्बक नेशनल डेटा सेंटर के माध्यम से प्रति घंटा अंतराल पर लगातार ट्रैक किया जा रहा है, इन्हें नियमित स्क्लफ्फ्डर जारी किए जा रहे हैं।

मंत्रालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) के माध्यम से स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जिसमें प्रमुख भारतीय बंदरगाहों, समुद्री अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय है। भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ-साथ भारतीय समुद्री यात्रियों वाले विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए उन्नत निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र सक्रिय किए गए हैं ताकि निरंतर स्थितिजन्य जागरूकता और परिचालन तैयारी सुनिश्चित हो।

शिपिंग कंपनियों, जहाज संचालकों और रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंसियों (च्ढ़छ) को संवेदनशील क्षेत्रों में क्रू तैनाती में सावधानी बरतने, यात्रा-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन करने और समुद्री यात्रियों तथा उनके परिवारों के साथ नियमित संचार बनाए रखने की सलाह दी गई है।

भारतीय समुद्री यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित समन्वय तंत्र भी स्थापित किए गए हैं।

मंत्रालय ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (ऋड़3) और पश्चिम एशियाई गंतव्यों के लिए जा रहे जहाजों और कार्गो की स्थिति की भी समीक्षा की।

कुल मिलाकर भारत भर के बंदरगाह संचालन स्थिर बने हुए हैं। बंदरगाहों को निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और एक्ट व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

मेजर पोर्ट्स ने जहाजों की गतिविधियों पर शिपिंग लाइनों और जहाज एजेंटों के साथ समन्वय में निरंतर निगरानी, क्षेत्र में विकासों का रीयल-टाइम मूल्यांकन और जहाज तथा कार्गो स्थिति की नियमित रिपोर्टिंग सहित परिचालन उपाय लागू किए हैं। जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त भंडारण स्थान की व्यवस्था की गई है, जबकि रेफ्रिजरेटेड और नाशवान कार्गो ड्ढ्ढल्लश्लेंल्लीळ्ल३२ पर करीबी निगरानी की जा रही है ताकि आवश्यकता पर प्राथमिकता से हैंडलिंग सुनिश्चित हो।

मंत्रालय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय में सभी घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए रख रहा है ताकि भारतीय समुद्री हितों की रक्षा हो, समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और समुद्री व्यापार तथा लॉजिस्टिक्स संचालन सुचारू रूप से चले।

टाइगर रिजर्व में वन टीम पर जानलेवा हमला: वन दरोगा गंभीर घायल, ग्राम प्रधान समेत 64 पर मुकदमा

(जीएनएस)।

पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) की माला रेंज में अवैध घुसपैठ और शिकार रोकने गई वन विभाग की टीम पर सौ से अधिक लोगों ने लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हिंसक घटना में वन दरोगा अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हमलावर मृत समझकर मौके पर छोड़ गए। न्यूरिया थाना पुलिस ने ग्राम प्रधान मेवाराम सहित 13 नामजद और 64 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, जानलेवा हमला और संपत्ति नुकसान की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।घटना 3 मार्च की रात करीब 8:30 बजे माला रेंज की वन कटी चौकी के आसपास हुई। गश्त पर तैनात वन

दरोगा अमित कुमार को सूचना मिली कि ग्राम मरौरी से बड़ी संख्या में लोग हथियारों के साथ जंगल में शिकार और लकड़ी चोरी के लिए घुस रहे हैं। वन रक्षक सचिन सिंह, डिप्टी रेंजर शेर सिंह और टाइगर ट्रेकर धर्मेंद्र के साथ टीम मरौरी क्रासिंग मचान पहुंची और भीड़ को रोकने की कोशिश की।तभी उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया। वन दरोगा अमित कुमार और ट्रेकर धर्मेंद्र को बुरी तरह पीटा गया, जबकि डिप्टी रेंजर की सरकारी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों ने टीम को जान से मारने की धमकी दी। बाद में वे मचान पर लौटे और बाइक, साइकिल, कुर्सियां, दरवाजा व नल तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया। एक साइकिल भी लूट ली गई।घायल अमित कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य वन संरक्षक पी.पी. सिंह, बरेली ने बताया, "गश्त के दौरान टीम पर मारपीट हुई। मुकदमा दर्ज है, पुलिस विवेचना के साथ विभागीय कार्रवाई होगी।" पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व कार्यालय में हंगामा: लिपिक पर महिला कर्मचारी को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप, हाथापाई तक पहुंचा विवाद

(जीएनएस)।

पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुख्य कार्यालय में शुक्रवार को संविदा महिला कर्मचारी के पति ने लिपिक सर्वेश पर मानसिक उत्पीड़न और आपत्तिजनक मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई, जिससे कार्यालय का कामकाज कुछ देर के लिए ठप हो गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला के पति को लिपिक की कथित आपत्तिजनक चैट मिलने पर वह सीधे कार्यालय पहुंचा और सर्वेश

से भिड़ गया। महिला कर्मचारी ने बताया कि लिपिक काफी समय से उसे मोबाइल पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से वह चुप थी, लेकिन हरकतें बढ़ने पर मामला खुल गया।वहीं, आरोपी लिपिक सर्वेश ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि संविदा महिला कर्मचारियों की छुट्टी की मांग को लेकर कहासुनी हुई थी। आपत्तिजनक मैसेज या गलत चैट के दावों को उन्होंने मनगढ़ंत करार दिया।प्रभारी फील्ड डायरेक्टर पी.पी. सिंह ने बताया कि मामला अभी औपचारिक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हंगामे की सूचना मिली है। विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।

संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत,पीड़ित परिवार ने हत्या का आरोप लगाया

(जीएनएस)।

पीलीभीत पूरनपुर। सेहरामऊ थाना क्षेत्र के रानीगंज निवासी अर्जुन पुत्र सोहनलाल जो पांच माह पहले महाराष्ट्र प्रदेश में मजदूरी करने गए थे वहां सुबह शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है ग्रामीणों से जानकारी के अनुसार जो लोग साथ में गए हुए थे उन लोगों से

भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजन साथ में ले जाने वाले लोगों पर ही हत्या की आसंका जता रहे हैं।

जनपद पीलीभीत के थाना सेहरामऊ क्षेत्र के रानीगंज का पूरा मामला है जहां 20 वर्षीय निवासी अर्जुन लगभग 5 महीने पहले महाराष्ट्र में मजदूरी करने गए थे वहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अर्जुन गरीब परिवार से हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे वहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

'टीडीबी-डीएसटी ने लिथियम-आयन बैटरियों के सतत पुनर्चक्रण हेतु मिनीमाइन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सहायता प्रदान की'

(जीएनएस)।

महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने "बेकार पड़ी लिथियम-आयन बैटरियों का सतत पुनर्चक्रण" नामक परियोजना के लिए मेसर्स मिनीमाइन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

इस परियोजना का उद्देश्य उपयोग के बाद बेकार हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे बैटरी-ग्रेड लवणों को निकालने हेतु स्वदेशी, शून्य-निर्वहन वाली, बैटरी के टिकाऊ पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज के शोधन की प्रक्रिया का व्यावसायीकरण करना है। इस पहल से पुनर्चक्रण की उन्नत प्रौद्योगिकियों के जरिए मूल्यवान महत्वपूर्ण खनिजों को फिर से प्राप्त करने की भारत की क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

हाइड्रोमेटलर्जीएम नामक एक विशेष प्रक्रिया विकसित की है, जो विभिन्न प्रकार के लिथियम-आयन बैटरियों के रसायन और आकार के अनुरूप है। इस कंपनी की ब्लैक

मिनीमाइन्स क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आर4 श्रेणी की पहली ऐसी पुनर्चक्रण करने वाली (रिसाइक्लर) कंपनी है जो उपयोग के बाद बेकार हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) सेवाएं सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करती है। इस कंपनी ने हाइब्रिड मास रिकवरी और पोस्ट-प्रोसेसिंग तकनीक कम ऊर्जा खपत, न्यूनतम उत्सर्जन और उच्च पृथक्करण दक्षता सुनिश्चित करती है, जिससे 99 प्रतिशत तक की पुनप्राप्ति (रिकवरी) दर हासिल होती है।

पूर्व-मूल्यांकन, संग्रहण तथा पृथक्करण से लेकर यांत्रिक प्रसंस्करण एवं निष्कर्षण, चयनात्मक पृथक्करण और खनिज संवर्धन (बेनेफिशिएशन) जैसे प्रसंस्करण के बाद वाले उन्नत चरणों तक की संपूर्ण प्रक्रिया स्वदेशी रूप से विकसित और पेटेंट कराई गई है। यह दृष्टिकोण आयातित पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता को काफी हद तक कम करने के साथ-साथ देश के भीतर शहरी खनन की अवधारणा को बढ़ावा देता है।

इस परियोजना के तहत, कंपनी अपने मौजूदा संचालन प्रक्रिया को एक पूर्णतः एकीकृत वाणिज्यिक संयंत्र के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव करती है, जो कई प्रकार की बैटरियों की रसायन प्रक्रियाओं को संसाधित करने और पुनः उपयोग के हेतु उच्च शुद्धता वाले महत्वपूर्ण पदार्थों का उत्पादन करने में सक्षम होगा। लिथियम कार्बोनेट और कोबाल्ट सल्फेट सहित पुनर्प्राप्त बैटरी-ग्रेड यौगिक संबंधित उद्योग के निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे और घरेलू एवं निर्यात, दोनों प्रकार के बाजारों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

इस अवसर पर बोलते हुए, टीडीबी के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा, 'उपयोग के बाद बेकार हो चुकी बैटरियों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति एवं शोधन हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को मजबूत करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के जरिए, टीडीबी पुनर्चक्रण के एक स्थायी समाधान के व्यावसायीकरण को सहायता प्रदान कर रहा है जो आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों में योगदान दे सकता है।'

एमपीएलएडीएस ईसाक्षी पोर्टल का नया सार्वजनिक डैशबोर्ड

(जीएनएस)।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए 1 अप्रैल 2023 से एमपीएलएडीएस-ईसाक्षी वेब पोर्टल (६६६.स'रि'ड्ढह्य.ड्ढ५.ल्ल) शुरू किया गया था। ईसाक्षी पोर्टल शुरू होने के साथ, माननीय सांसदों की वार्षिक पात्रता प्रत्येक वित्तीय वर्ष या कार्यकाल की शुरुआत में ऑनलाइन प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

ई-साक्षी पोर्टल योजना के सभी हितधारकों को लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करता है, जिनमें माननीय सांसद, केंद्रीय नोडल एजेंसी, (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) राज्य नोडल प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल हैं। माननीय सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र विकास कार्यों की अनुशंसा करने और अपने वार्षिक आवंटन से धनराशि आवंटित करने के लिए पोर्टल का उपयोग करते हैं। माननीय सांसदों के लिए, पोर्टल पर अनुशंसित कुल राशि योजना के तहत उन्हें आवंटित धनराशि के उपयोग को दर्शाती है।

अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों की होती है। आवश्यक कार्यवाही करने के बाद, जिला अधिकारी कार्यों की स्वीकृति देते हैं और निष्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को नामित करते हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत कार्यों को सामान्यतः स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा करना आवश्यक होता है।

कार्यान्वयन एजेंसियां जिला अधिकारियों द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों के अनुसार, कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में पोर्टल पर विक्रेता भुगतान अनुरोध प्रस्तुत करती हैं। डैशबोर्ड पर प्रदर्शित व्यय आंकड़े पूर्ण और चल रहे कार्यों के लिए जारी किए गए कुल विक्रेता भुगतानों को दर्शाते हैं।

1 अप्रैल 2023 से पहले, एमपीएलएडीएस योजना को व्यवहारिक रूप से लागू किया गया था। अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों से संबंधित जानकारी जिलावार सम्बंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा रखी जाती थी और व्यय जिला स्तर पर रखे गए भौतिक बैंक खातों के माध्यम से किया जाता था।

फिट इंडिया कार्निवल अपने दूसरे भव्य संस्करण के साथ नई दिल्ली में वापसी करेगा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 64वें विशेष 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम की भी तैयारी चल रही है

"सभी के लिए फिटनेस" के उद्देश्य से फिट इंडिया कार्निवल वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ हो गया है

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य, खेल और सामुदायिक भावना का एक जीवंत उत्सव देखने को मिलेगा क्योंकि फिट इंडिया कार्निवल का दूसरा संस्करण इस रविवार को नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में शुरू हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर को मना रहा है।

तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन रविवार को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 64वें संस्करण के समापन के बाद होगा। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी किया जा रहा है। इस संस्करण में महिला एथलीटों, इन्फ्लुएंसर्स और फिटनेस चैंपियनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, खेल सचिव श्री हरि रंजन राव और कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में फिट इंडिया कार्निवल 2.0 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन दिवस पर कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें सदाबहार अभिनेता और मॉडल श्री मिलिंद सोमन, प्रसिद्ध अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी, ऐश्वर्या राज और तरुण खन्ना